

उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों के नामांकन-ड्रॉप आउट पर मध्याह्न भोजन योजना का
प्रभाव : एक अध्ययन

1प्रतिमा सिंह एवं 2डॉ० हेमलता सांगुडी

¹शोध-छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

²सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डी० बी० एस० कॉलेज, कानपुर।

शोध सार :- यह शोध-पत्र भारत में लागू किए गए दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त स्कूल भोजन कार्यक्रम, जिसे मिड-डे-मील योजना के नाम से जाना जाता है, के स्कूल नामांकन एवं ड्रॉप-आउट पर प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया गया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों और स्थानों पर भिन्नताएँ देखी गई हैं। इस अध्ययन में एक साधनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, यह विश्लेषण किया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन-ड्रॉप आउट पर स्कूल में मुफ्त भोजन प्राप्त करने के प्रभाव का क्या प्रभाव है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि यह कार्यक्रम बच्चों के शिक्षा में नामांकन को कैसे प्रभावित करता है और इसके विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट को कम करने में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना ने उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन की संभावना को बढ़ाने के साथ-साथ वर्ग अध्ययन को बीच में नहीं छोड़ने को भी प्रोत्साहित किया है। परिणामों के विविधता के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम का प्रभाव विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचित समूहों और लड़कियों पर अधिक गहरा था। विश्लेषण में यह भी पाया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का लड़कियों पर गहरा प्रभाव हुआ है, उनके नामांकन के संदर्भ में लड़कों की तुलना में लगभग दोगुना था। यह तथ्य इस बात का संकेत है कि इस कार्यक्रम ने विद्यालय में भागीदारी के मामले में लड़का एवं लड़कियों के बीच के अंतर को कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई है।

शब्द कुंजी :- मध्याह्न भोजन योजना, उच्च प्राथमिक विद्यालय, नामांकन, ड्रॉपआउट, छात्र-छात्रा, वंचित समूह, प्रभाव।

1. प्रस्तावना :-

मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में देश के 2408 ब्लॉकों में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को पोषण प्रदान करना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। वर्ष 1997-98 तक, यह कार्यक्रम सभी ब्लॉकों में लागू किया गया, वर्ष 2003 में, इस योजना का विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों तक किया गया, जिससे उन बच्चों को भी लाभ मिला जो

पारंपरिक स्कूलों में नहीं पढ़ रहे थे। अक्टूबर 2007 से, इसे देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा-6 से कक्षा-8 के छात्रों तक बढ़ा दिया गया। 2008-09 से, यह योजना देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो गई, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी 01.04.2010 से प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना में शामिल किया गया, जिससे बाल श्रम के शिकार बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। इस प्रकार, मध्याह्न भोजन योजना ने शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को मध्याह्न के समय गर्म और पका हुआ भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ सके, उन्हें अधिक समय तक विद्यालय में रोका जा सके और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह योजना छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न जातियों और धर्मों के छात्रों को एक साथ भोजन करने का अवसर प्रदान करके उनके बीच सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास भी करती है।

2. संबंधित साहित्य

भाटिया रचना और अइयर उमा (2016) ने यह निष्कर्ष निकाला कि मध्याह्न भोजन योजना में रसोइयों के रूप में मुख्यतः दीन-हीन विधवाओं को नियुक्त करना उनके लिए रोजगार के समान है, और इससे बच्चों के नामांकन और उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। समस्या केवल बच्चों को पोषणयुक्त भोजन के वितरण की उचित देखरेख से संबंधित है।

दत्ता के अनुसार, 2015 में मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे आमतौर पर मिड डे मील के नाम से जाना जाता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवंबर 1995 के बाद से राज्य में लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपस्थित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनके सीखने के स्तर को बढ़ाना और उन्हें आवश्यक पोषण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम न केवल बच्चों के शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके मानसिक विकास और शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से, बच्चों को एक संतुलित आहार मिलता है, जो उनकी समग्र वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है।

रामटेक वन्दना (2015) ने नागपुर शहर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के विद्यालयों का विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने यह पाया कि मध्याह्न भोजन योजना ने छात्रों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि के साथ-साथ उनकी अच्छी आदतों को विकसित करने और कक्षा में भूख की समस्या को समाप्त करने में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ शिक्षकों पर बढ़ते बोझ ने उनके शिक्षण कार्य में कुछ रुकावटें भी उत्पन्न की हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

उमा (2013) के अनुसार, मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और स्वास्थ्य में सुधार करना है। हालांकि, इस योजना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जबकि योजना बच्चों को स्कूल में लाने और उनकी सेहत को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार, यह योजना केवल बच्चों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया जा रहा है।

श्रीनिवासन 2010 ने अपने अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया है। उनके शोध के अनुसार, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य स्कूलों में भूख और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, गरीब बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना और उनकी उपस्थिति दर को बढ़ाना है। हालांकि, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस योजना के माध्यम से स्कूलों में भूख और बच्चों के पोषण स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है।

लाथ राहुल (2006) ने इस शोधपत्र में मध्याह्न भोजन योजना को विद्यालयों में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि बच्चों को पोषण से भरपूर आहार प्रदान करने के लिए इस योजना को सही और उपयुक्त स्थानों पर लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को नियमित जांच और नई तकनीकों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

3. मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत साप्ताहिक भोजन मेन्यू

जनपद गोण्डा के विकासखण्ड गोण्डा के चयनित कुछ गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं द्वारा दिखाया गया है।

तालिका-1

साप्ताहिक आहार तालिका (मेन्यू)

दिन	नवीन मेन्यू	व्यंजन का प्रकार
सोमवार	रोटी-सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग	100 ग्राम गेहूँ की रोटी एवं दाल (दाल में मौसमी सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन
मंगलवार	चावल सब्जी युक्त दाल अथवा चावल साम्भर	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (मौसमी) मिश्रित दाल, अरहर की दाल साम्भर मशाला एवं मौसमी सब्जी
बुधवार	कढ़ी चावल अथवा खीर	100 ग्राम चावल, बेसन, मट्ठा/दही कढ़ी मानकानुसार दूध, चीनी मेवे का मिश्रण

गुरुवार	रोटी-सब्जीयुक्त दाल	100 ग्राम. गेहूँ की रोटी एवं दाल (दाल में मौसमी सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन
शुक्रवार	तहरी	100 ग्राम. चावल एवं सब्जी (आलू सोयाबीन एवं समय-समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियाँ)
शनिवार	सब्जी-चावल, सोयाबीन अथवा खीर	100 ग्राम चावल एवं सोयाबीन तथा मसाले एवं ताजी सब्जियों का प्रयोग किया जाए

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, जनपद गोण्डा।

4. शोध उद्देश्य -

प्रस्तुत शोधपत्र में शोधकर्ता ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं :-

1. मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन का विश्लेषण करना।
2. नामांकन पर मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. विद्यालय में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति एवं ठहराव पर मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव ज्ञात करना।

5. अध्ययन पद्धति :-

मध्याह्न भोजन योजना से विद्यालयों में नामांकन, ठहराव आदि का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का उपयोग करते हुए एक सौ छात्रों से डेटा एकत्र किया है। इस 100 बच्चों के समूह में 57 लड़कियाँ और 45 लड़के शामिल हैं, जिनमें से 20 बच्चे अनुसूचित जाति, 69 बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग, और 11 बच्चे सामान्य वर्ग से संबंधित हैं।

6. आंकड़ों का विश्लेषण :-

तालिका 2 : भोजन संबंधी विवरण

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	आपको स्कूल में क्या खाना दिया जाता है?	हाँ- 100 प्रतिशत नहीं- 0 प्रतिशत
2.	क्या खाना आपको खाने में अच्छा लगता है?	हाँ- 100 प्रतिशत नहीं- 0 प्रतिशत
3.	खाना मिलने में कितना समय लगता है?	20 मिनट
4.	खाना खाने के लिए कितना समय दिया जाता है?	60 मिनट
5.	क्या स्कूल में आपको भरपेट खाना मिलता है?	हाँ- 100 प्रतिशत नहीं- 0 प्रतिशत

6.	क्या खाना आप घर पर भी ले जाते हैं?	हाँ- 0 प्रतिशत नहीं- 100 प्रतिशत
7.	क्या आप स्कूल सिर्फ खाना बंटने के समय ही जाते हैं?	हाँ- 0 प्रतिशत नहीं- 100 प्रतिशत
8.	क्या आपके साथ ऐसे बच्चे भी खाना खाने जाते हैं। जिनका स्कूल में नाम नहीं लिखा है?	हाँ- 0 प्रतिशत नहीं- 100 प्रतिशत
9.	क्या स्कूल में खाना दिया जाना चाहिए?	हाँ- 100 प्रतिशत नहीं- 0 प्रतिशत
10.	क्या खाना खाने से आपके स्कूल में कोई बीमार भी पड़ा है?	हाँ- 0 प्रतिशत नहीं- 100 प्रतिशत
11.	क्या खाना खाने के लिए आप बर्तन घर से ले जाते हैं?	हाँ- 0 प्रतिशत नहीं- 100 प्रतिशत

शोधकर्ताओं के अध्ययन से यह पता चला है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी उपस्थित बच्चों को विद्यालय में भोजन प्रदान किया जाता है। सभी बच्चों को यह भोजन पसंद आता है। भोजन प्राप्त करने में बच्चों को 20 मिनट का समय लगता है। खाने के लिए बच्चों को 1 घंटे का समय दिया जाता है। 100 प्रतिशत बच्चों ने बताया है कि विद्यालय में मिलने वाले भोजन के सेवन से कोई भी बीमार नहीं हुआ है। सभी बच्चों को विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में खाना दिया जाता है। सभी बच्चों ने बताया कि वे खाना घर नहीं ले जाते, बल्कि विद्यालय में ही भोजन करते हैं। सभी बच्चों का यह कहना था कि वे विद्यालय के खुलने के समय पर ही पहुंच जाते हैं। विद्यालय में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका नाम स्कूल में दर्ज न हो और फिर भी वह खाना खाता हो। 78 प्रतिशत बच्चों ने यह जानकारी दी कि शिक्षक भी उनके साथ भोजन करते हैं, जबकि 22 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि शिक्षक खाना नहीं खाते हैं।

तालिका 3 : शैक्षिक स्तर नामांकन एव ठहराव

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	स्कूल में पढ़ाई के लिए कितने घंटे लगते हैं?	7 घण्टे
2.	खाना मिलने से पहले कितने घंटे पढ़ाई होती है?	4 घण्टे
3.	खाना मिलने से बाद कितने घंटे पढ़ाई होती है?	3 घण्टे
4.	स्कूल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से क्या आपकी पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता है?	हाँ- 0 प्रतिशत नहीं- 100 प्रतिशत
5.	स्कूल में एक वक्त का खाना मिलने से बच्चों की पोषणीयता में वृद्धि हुई है।	हाँ- 100 प्रतिशत नहीं- 0 प्रतिशत

6.	स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने की वजह से बच्चों के पंजीकरण संख्या में वृद्धि हुई है?	हाँ— 100 प्रतिशत नहीं— 0 प्रतिशत
7.	मध्याह्न भोजन करने के पश्चात् भी आप घर चले जाते हैं?	हाँ— 30 प्रतिशत नहीं— 70 प्रतिशत
8.	क्या आपके साथ आपके शिक्षक भी खाना खाते हैं ?	हाँ— 38 प्रतिशत नहीं— 62 प्रतिशत

विद्यालय में अध्ययन के लिए 7 घंटे निर्धारित हैं, जिसमें से 4 घंटे भोजन से पहले और 3 घंटे भोजन के बाद होते हैं। एक शोध के दौरान, 84 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि शिक्षक कुछ बच्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि 16 प्रतिशत ने इस बात का विरोध किया। सभी बच्चों का यह मानना है कि विद्यालय में भोजन की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी बच्चों ने यह भी कहा कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से उनकी पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

जो बच्चे पहले घर से भूखे आते थे या स्कूल पहुँचते-पहुँचते भूखे हो जाते थे, अब उन्हें भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल में उन्हें भोजन उपलब्ध होने के कारण वे अब स्कूल आना अधिक पसंद करते हैं। इस बदलाव के परिणामस्वरूप बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

शोध के निष्कर्षों के अनुसार, लगभग 57 प्रतिशत लड़कियाँ विद्यालय में पंजीकृत हैं। वर्तमान में, बच्चे पूरे समय विद्यालय में उपस्थित रहते हैं और पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ते। अधिकांश बच्चे अब विद्यालय जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं और नियमित रूप से वहाँ उपस्थित होते हैं। फिर भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मध्याह्न भोजन के बाद घर लौट जाते हैं, और इन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि वे अपनी शिक्षा को जारी रख सकें।

लगभग 38 प्रतिशत बच्चों का यह मानना है कि उनके शिक्षक स्कूल में भेदभाव करते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। यह स्थिति बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा, स्कूल में बच्चों को जो भोजन दिया जाता है, उसे सभी शिक्षक नहीं खाते हैं; केवल 38 प्रतिशत शिक्षक ही बच्चों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। यह तथ्य भी दर्शाता है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच की दूरी और भेदभाव की भावना को बढ़ावा मिल सकता है, जो कि एक स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है।

7. निष्कर्ष :-

मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। यह योजना गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ एक समय का भोजन प्रदान करके उनकी पोषण स्थिति में

सुधार कर रही है। इसके परिणामस्वरूप भूखमरी की समस्या में भी कमी आ रही है। मध्यान्ह भोजन योजना के कार्यान्वयन में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि भोजन की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, स्वाद में कमी होना, मेन्यू में विकल्पों की अत्यधिक सीमितता, बच्चों का भोजन खाने के बाद बीमार पड़ना या यहां तक कि उनकी मृत्यु होना, खाना बनाने में स्वच्छता का अभाव, और भोजन मिलने से बच्चों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना। इन सभी कारणों से यह योजना अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में असफल हो रही है।

मध्यान्ह भोजन योजना बहुत अच्छी है तथा यदि इसे सही से कार्यान्वित किया जाए तो यह अपने उद्देश्यों को पाने में सफल हो सकती है। भारत जो कि एक अल्पविकसित देश है, जहाँ की लगभग 29 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। इस योजना से इनके बच्चों को एक गुणात्मक मानव संसाधन बनाकर भारत को विकसित करने में ज्यादा मदद मिलेगी। किन्तु मध्यान्ह भोजन योजना के प्रारूप एवं क्रियान्वयन व्यवस्था को इस प्रकार प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है जिससे कि यह कार्यक्रम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु साथ 'क उत्प्रेरक की भूमिका निभा कर सार्वभौम प्रवेश, उपस्थिति अधिगम तथा सबके लिये स्वास्थ्य जैसे सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें। मध्यान्ह भोजन योजना के कार्यान्वयन में मौजूद सीमाएं इसकी असफलता की कहानी को उजागर कर रही हैं।

8. सुझाव :-

शिक्षकों का यह मानना है कि मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था में अधिक समय लगने के कारण वे बच्चों को उचित ध्यान और समय नहीं दे पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, यह आवश्यक है कि मध्यान्ह भोजन के संचालन के लिए शिक्षकों के अलावा विशेष रूप से अलग कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही, बच्चों को प्रदान किए जाने वाले भोजन को पकाने से पूर्व उसकी अच्छी तरह से सफाई करना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में सफाई के मानकों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, भोजन की गुणवत्ता भी उच्च स्तर की होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिल सके। जनपद और ब्लाक स्तर पर स्थापित टास्क फोर्स द्वारा हर महीने निरीक्षण करना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस में तैयार भोजन का नमूना विद्यालय के बंद होने तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पंचायती राज विभाग द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संदर्भ में 'निर्मल भारत अभियान' के तहत अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची :-

1. अदावल, सुबोध एवं उनियाल माघवेन्द्र (1974), भारतीय शिक्षा की समस्याएं तथा प्रवृत्तियाँ, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, पृ.सं. 225

2. लहरी, बिमल कुमार (2015), मध्यान्ह भोजन योजना एवं सामाजिक परिवर्तन, भारतीय प्रकाशन, वाराणसी, पृ.सं. 31-47
3. पाण्डेय, के.पी. (2006), 'शैक्षिक अनुसंधान', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
4. तिवारी, सुभाष चन्द (2005-06), "प्राथमिक स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन समस्या का अध्ययन", लघु शोध प्रबन्ध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. पाथवानी, अनीता एवं कुलवन्त (2006), "प्राइमरी शिक्षा और मिड-डे मील स्कीम : रिजल्ट, चैलेंजेज एवं सॉल्यूशन्स", दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. पाठक, पी.डी. (2009), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ.सं. 289
7. गुप्ता, एस.पी. (1996), भारतीय शिक्षा का विकास तथा समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
8. मित्तल, एस.एस. (1985), "Impact of Midday Meals Programme and Enrolment and Attendance at Primary Stage"
9. Lakshmi, S. (1982), 'Innovations on Education', Sterling Publishing, New Delhi
10. लहरी, विमल कुमार (2015), मध्यान्ह भोजन योजना एवं सामाजिक परिवर्तन भारतीय प्रकाशन, वाराणसी।
11. शर्मा, अंजना (2014), मध्यान्ह भोजन योजना का विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव—ग्वालियर जिले के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.